नंदिग्राम टाईम्स

RNI NO. MAHHIN/2016/69743 EDITOR : SHAIKH JAHUR AHEMAD

Sunday 4th January 2026 | ● वर्ष - 9 | ● अंक 249 | ● पृष्ठ 04 | ● मूल्य - 2 रूपए | ● www.nandigramtimes.com

सीजेआई सूर्यकांत: “सबसे ज्यादा जरूरतमंद लोगों तक न्याय पहुंचना चाहिए

भारत के प्रधान न्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत ने कहा कि न्यायपालिका का मुख्य उद्देश्य केवल मामलों का निपटारा करना नहीं, बल्कि न्याय को सबसे ज्यादा जरूरतमंद लोगों तक पहुँचाना है। उन्होंने यह बात पटना के चाणक्य राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय में दीक्षांत समारोह में कही।

सीजेआई ने बताया कि कानून प्रणाली में सहानुभूति और मानवीय दृष्टिकोण अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। उन्होंने युवा वकीलों को प्रेरित करते हुए कहा कि करियर में जोश और समर्पण जरूरी है, लेकिन संवेदनशीलता और नैतिक मूल्यों का नुकसान नहीं होना चाहिए। यदि इंसानियत की भावना खत्म हो जाए तो न्याय सही ढंग से नहीं हो सकता।

सूर्यकांत ने न्याय व्यवस्था को और मानवीय बनाने पर जोर दिया, ताकि आम लोग बिना भय और झिझक अपना हक प्राप्त कर सकें। उनका कहना था कि कानून और उसके सिद्धांतों का अध्ययन उतना ही जरूरी है जितना कि न्याय के मूल्यों को समझना।

IPL NEWS | मुस्तफिजुर को IPL में 'बैन' कर बांग्लादेश को तगड़ा कूटनीतिक संदेश?

मुस्तफिजुर को IPL में 'बैन' कर बांग्लादेश को तगड़ा कूटनीतिक संदेश? भारत ने कर दिया बड़े एक्शन का इशारा

नई दिल्ली: बांग्लादेशी तेज गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान को इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 से हटाने का निर्णय भारत में बड़ा राजनीतिक और कूटनीतिक विषय बन गया है। यह कदम केवल एक खेल संबंधी फैसला नहीं माना जा रहा, बल्कि भारत की ओर से बांग्लादेश को भेजा गया एक सशक्त संदेश भी बताया जा रहा है।

दिसंबर 2025 में कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) ने आईपीएल नीलामी में 30 वर्षीय बांग्लादेशी तेज गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान को ₹9.20 करोड़ में खरीदा था, लेकिन इस फैसले के बाद ही भारत में राजनीतिक और सामाजिक संगठनों का विरोध शुरू हो गया। विरोध का कारण बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों के खिलाफ कथित हिंसा और अत्याचारों की खबरें थीं, जिनके चलते कुछ संगठनों ने आईपीएल में रहमान के खेलने के खिलाफ अभियान छेड़ दिया।

इस बढ़ते विवाद के बीच भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने KKR को आधिकारिक दिशा-निर्देश जारी कर कहा कि वे मुस्तफिजुर को अपनी टीम से रिलीज़ करें। KKR ने BCCI के आदेश का पालन करते हुए रहमान को आईपीएल 2026 के सत्र से हटा दिया है और बोर्ड ने टीम को किसी अन्य विदेशी खिलाड़ी को शामिल करने की अनुमति देने का भी संकेत दिया है।

बॉर्डर पार हुई यह घटना भारत-बांग्लादेश संबंधों में तनाव की एक नई कड़ी के रूप में देखी जा रही है। भारत के कुछ राजनीतिक नेताओं ने इस फैसले का स्वागत किया और इसे भारत के सनातनियों की भावना की विजय बताया है, वहीं आलोचकों का कहना है कि खेल को राजनीति से अलग रखना चाहिए। बांग्लादेश में हिंदू समुदाय के खिलाफ कथित हिंसक घटनाएं — जैसे मैमनसिंह जिले में एक व्यक्ति की भीड़ द्वारा पीट-पीटकर हत्या — ने भारत में नाराजगी बढ़ा दी है। इन घटनाओं को लेकर सोशल मीडिया पर भी तीखी प्रतिक्रियाएं सामने आई थीं।

विश्लेषकों का मानना है कि यह IPL से हटाने का कदम भारत की ओर से एक कूटनीतिक संकेत भी है कि अगर बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा नहीं की गई, तो भारत अन्य अहम निर्णय भी ले सकता है। इसमें आर्थिक और ऊर्जा आपूर्ति जैसे मुद्दे शामिल हैं, जिनमें बांग्लादेश काफी हद तक भारत पर निर्भर है — विशेष रूप से बिजली और विभिन्न आवश्यक वस्तुओं के निर्यात पर।

हालांकि BCCI का यह फैसला खेल जगत में भी विवाद का विषय बन गया है। कुछ क्रिकेट विशेषज्ञ और प्रेमी इसे खेल की स्वतंत्रता पर आघात मानते हैं और मांग कर रहे हैं कि खेल और राजनीति को अलग रखना चाहिए। विरोध और समर्थन के बीच यह मुद्दा देश में और बांग्लादेश में भी गहरी चर्चा का विषय बना हुआ है।
\इस पूरी घटना ने न केवल खेल प्रेमियों का ध्यान आकर्षित किया है, बल्कि यह संकेत भी दिया है कि कैसे खेल, राजनीति और अंतरराष्ट्रीय रिश्ते एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और कब कोई खेल निर्णय बड़े कूटनीतिक प्रभाव का रूप ले सकता है।

125 साल बाद भारत की सांस्कृतिक विरासत लौटी — पीएम मोदी ने पवित्र बुद्ध अवशेषों का उल्लेख किया

NEWS AGENCY |

नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को दिल्ली के राय पिथोरा सांस्कृतिक परिसर में ‘The Light & The Lotus: Relics of the Awakened One’ नामक प्रदर्शनी का उद्घाटन किया, जहाँ भगवान बुद्ध से जुड़ी पवित्र धरोहरें प्रदर्शित की गईं। इन अवशेषों को भारत में लगभग 125 साल बाद वापस लाया गया है, जिसे मोदी ने अपनी प्रस्तुति में “भारत की विरासत घर लौटने जैसा” बताया।

पीएम मोदी ने कहा कि ये अवशेष केवल पुरातात्विक वस्तुएँ नहीं हैं, बल्कि भारत की सभ्यता और आध्यात्मिक परंपरा का अभिन्न हिस्सा हैं। उन्होंने बताया कि पिपरहवा से मिले पवित्र अवशेषों को विदेशों से वापस भारत लाया गया है, जहाँ वे लंबे समय तक रखे गए थे। यह प्रयास भारत सरकार और गोदरेज समूह के सहयोग से संभव हुआ, जब उन्होंने अगले साल मई में इन वस्तुओं की नीलामी रोक दी थी।

प्रधानमंत्री ने बौद्ध भिक्षुओं और अन्य अतिथियों को संबोधित करते हुए कहा कि बुद्ध की यह साझा विरासत दुनिया भर के लोगों को शांति, आस्था और भावनात्मक जुड़ाव की याद दिलाती है। उन्होंने याद दिलाया कि भारत न केवल बौद्ध धर्म का जन्मस्थल है, बल्कि उसकी गहन सांस्कृतिक और आध्यात्मिक धरोहर का संरक्षक भी है। प्रदर्शनी में धर्म से जुड़ी पुरातन अवशेषों के साथ-साथ बहुमूल्य रत्न, सोने-चांदी के आभूषण और अन्य भारतीय पुरातत्व सामग्रियाँ भी शामिल हैं, जिन्हें अब जनता के दर्शन के लिए खोला गया है। मोदी ने इसे भारतीय संस्कृति और इतिहास का “उत्कृष्ट उदाहरण” बताया, जो आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनेगा।

6 सालों में भारतीयों को 52 हजार करोड़ का नुकसान, किन राज्यों में सबसे ज्यादा हुआ साइबर फ्रॉड?

नई दिल्ली: पिछले छह वर्षों में विभिन्न धोखाधड़ी और जालसाजी के मामलों में भारतीयों को 52,976 करोड़ रुपए से अधिक का नुकसान हुआ है, जिसमें महाराष्ट्र में सबसे अधिक वित्तीय नुकसान दर्ज किया गया है। शनिवार को एक रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ है।

इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर द्वारा नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल से संकलित आंकड़ों के अनुसार, 2025 में लगभग 19,813 करोड़ रुपए का नुकसान और धोखाधड़ी से संबंधित 2,177,524 शिकायतें दर्ज की गईं।

2024 में दर्ज की गई 1,918,852 शिकायतें
2024 में दर्ज नुकसान 22,849.49 करोड़ रुपए था और 1,918,852 शिकायतें दर्ज की गईं। इससे पहले के वर्षों में कम राशि दर्ज की गई थी, जो फाइनेंशियल क्राइम्स, डिजिटल अरेस्ट, ऑनलाइन स्कैम और बैंकिंग फ्रॉड जैसे वित्तीय अपराधों में चिंताजनक वृद्धि की ओर इशारा करती है। विश्लेषकों ने इस तीव्र वृद्धि का कारण तेजी से डिजिटलीकरण और ऑनलाइन लेनदेन में वृद्धि को बताया है।
एक रिपोर्ट के अनुसार, आंकड़ों से पता चला है कि पिछले साल धोखाधड़ी के मामलों में महाराष्ट्र को सबसे अधिक आर्थिक नुकसान हुआ, जो 3,203 करोड़ रुपए था, और इसके लिए 2,833,20 शिकायतें दर्ज की गईं। इसके बाद कर्नाटक का स्थान रहा, जहां 2,413 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ और 2,132,28 शिकायतें दर्ज की गईं।

उत्तर प्रदेश में 1,443 करोड़ का नुकसान
रिपोर्ट में कहा गया है कि तमिलनाडु में 1,897 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ और 123,290 शिकायतें दर्ज की गईं। उत्तर प्रदेश में 1,443 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ और 275,264 शिकायतें दर्ज की गईं और तेलंगाना में 1,372 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ और 95,000 शिकायतें दर्ज की गईं। ये शीर्ष पांच राज्य राष्ट्रीय कुल नुकसान के आधे से अधिक के लिए जिम्मेदार हैं।

आंकड़ों से पता चला है कि 19,812 करोड़ रुपए में से 77 प्रतिशत निवेश योजनाओं के नाम पर, 8 प्रतिशत डिजिटल अरेस्ट के माध्यम से, 7 प्रतिशत क्रेडिट कार्ड धोखाधड़ी से, 4 प्रतिशत सेक्सटॉर्शन से, 3 प्रतिशत ई-कॉमर्स धोखाधड़ी से और 1 प्रतिशत ऐप/मैलवेयर आधारित धोखाधड़ी से हुआ।

5 चुनावी राज्यों के लिए कांग्रेस ने बनाई स्क्रीनिंग कमेटी, प्रियंका को मिली बड़ी जिम्मेदारी

नई दिल्ली: कांग्रेस ने केरल, असम, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और पुडुचेरी के विधानसभा चुनावों के लिए शनिवार को स्क्रीनिंग कमेटी का गठन किया। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाद्रा को असम के लिए बनाई गई स्क्रीनिंग कमेटी की अध्यक्षता सौंपी गई है।

पार्टी के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल की ओर से जारी विज्ञप्ति के अनुसार, असम से संबंधित स्क्रीनिंग कमेटी में प्रियंका गांधी के साथ सप्तगिरि उलाका, इमरान मसूद और श्रीवेला प्रसाद को बतौर सदस्य शामिल किया गया है।

केरल के लिए मुधुसूदन मिस्त्री को सौंपी गई कमान
कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मधुसूदन मिस्त्री की अध्यक्षता में केरल के लिए गठित स्क्रीनिंग कमेटी में सैयद नासिर हुसैन, नीरज डांगी और अभिषेक दत्त को शामिल किया गया है।

टीएस सिंहदेव को दी गई तमिलनाडु और पुडुचेरी की जिम्मेदारी
छत्तीसगढ़ के पूर्व उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव को तमिलनाडु और पुडुचेरी से संबंधित स्क्रीनिंग कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया है। यशोमती ठाकुर, जी सी चंद्रशेखर और अनिल कुमार यादव को बतौर सदस्य शामिल किया गया है।

बी के हरिप्रसाद को पश्चिम बंगाल की जिम्मेदारी दी गई
कांग्रेस के वरिष्ठ नेता बी के हरिप्रसाद को पश्चिम बंगाल के लिए बनी स्क्रीनिंग कमेटी की अध्यक्षता सौंपी गई है। मोहम्मद जावेद, ममता देवी और बी पी सिंह को भी इस कमेटी में जगह दी गई है। स्क्रीनिंग कमेटी हर सीट पर टिकट के लिए दावेदारी करने वालों में से कुछ लोगों के नाम पार्टी केंद्रीय चुनाव समिति के पास भेजती है, जहां उम्मीदवार के नाम पर मुहर लगती है। केरल, असम, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और पुडुचेरी राज्यों में इस वर्ष मार्च-अप्रैल में विधानसभा चुनाव संभावित है।

2026 में होने वाले इन विधानसभा चुनावों के जरिए कांग्रेस एक बार फिर कमबैक की तैयारी कर रही है। इसके लिए पार्टी बेरोजगारी, मनरेगा जैसे मुद्दों पर जनता का ध्यान आकर्षित कर सकती है। हालांकि कांग्रेस के सामने संगठन से लेकर गठबंधन की पार्टियों को मजबूत करना एक चुनौती होगी।

AIIMS शोध में बड़ा खुलासा: भारत में युवाओं में अचानक मौत का प्रमुख कारण हृदय रोग

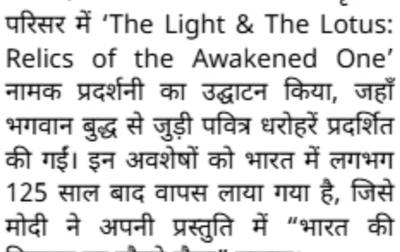

नई दिल्ली: AIIMS के हालिया शोध में खुलासा हुआ है कि भारत में 18 से 45 वर्ष के युवाओं में अचानक मौतों का सबसे बड़ा कारण हृदय रोग है। अध्ययन में पाया गया कि लगभग 42.6% मौतें हृदय संबंधी बीमारियों—जैसे दिल की धमनियों में 70% से अधिक रुकावट—के कारण हुईं। वहीं, 21.3% मौतें सांस संबंधी बीमारियों जैसे निमोनिया, टीबी और अस्फ़िक्सिया के कारण हुईं, और लगभग 20% मामलों में कारण स्पष्ट नहीं हो सका।

विशेषज्ञों का कहना है कि युवाओं में अचानक मौतें अक्सर बिना चेतावनी संकेत होती हैं, जबकि कई मृतक स्वस्थ प्रतीत होते थे। शोध में यह भी पाया गया कि कोविड-19 संक्रमण या टीकाकरण का इन मौतों से कोई संबंध नहीं है। विशेषज्ञों ने युवाओं को नियमित स्वास्थ्य जांच, तनाव-मुक्त जीवन और स्वस्थ जीवनशैली अपनाने की सलाह दी है।

दिल्ली दंगा मामले में सुप्रीम कोर्ट 5 जनवरी को सुनाएगा जमानत याचिका पर फैसला

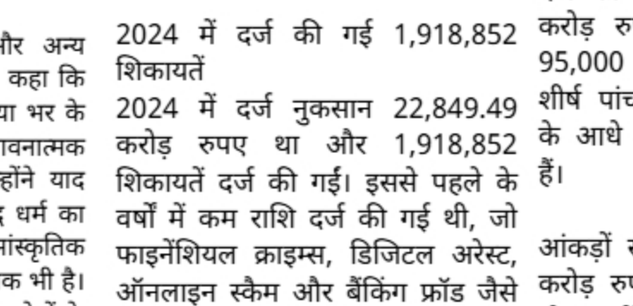

नई दिल्ली: उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों 2020 से जुड़े उमर खालिद, शरजील इमाम तथा अन्य आरोपियों की जमानत याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट 5 जनवरी सोमवार को अपना फैसला सुनाने जा रहा है। यह मामला ‘बड़ी साजिश (larger conspiracy)’ से जुड़ा है, जिसमें आरोपियों पर गैरकानूनी गतिविधि (निवारण) अधिनियम (UAPA) समेत गंभीर धाराओं के तहत मुकदमा चल रहा है।

मुख्य रूप से अदालत ने 10 दिसंबर 2025 को दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रखा था। इस मामले में वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल, अभिषेक सिंहवी और सिद्धार्थ दवे की ओर से आरोपियों के पक्ष में दलील दी गई थी, जबकि दिल्ली पुलिस की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और एएसजी एस.वी. राजू ने मजबूत तरीके से जमानत का विरोध किया।
याचिकाकर्ताओं ने कोर्ट में तर्क दिया है कि उन्हें लंबी अवधि से बिना दोष सिद्ध किए हिरासत में रखा गया है, जिससे उनके मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है। वकीलों ने यह भी कहा कि अभी तक ट्रायल की प्रक्रिया शुरू नहीं हुई है और उन्हें अपूरणीय हानि हो रही है। विशेष रूप से उमर खालिद के वकील ने यह दावा किया कि दंगों के समय वह दिल्ली में मौजूद नहीं थे, जबकि शरजील इमाम की तरफ से यह कहा गया कि उनके भाषणों को गलत तरीके से हिंसा भड़काने वाला बताया जा रहा है। दिल्ली पुलिस का कहना है कि फरवरी 2020 के दंगे स्वयं-सिद्ध नहीं थे, बल्कि पूर्व नियोजित, सुनियोजित और सुविचारित हमले का हिस्सा थे, इसलिए जमानत देना उचित नहीं है। पुलिस ने यह भी दलील दी कि सभी आरोपी एक दूसरे की साजिश में शामिल हैं और उनके खिलाफ साक्ष्य मौजूद हैं।

दिल्ली हाईकोर्ट पहले ही 2 सितंबर 2025 को इन सभी आरोपियों की जमानत याचिकाएँ खारिज कर चुका है, जिसके बाद आरोपियों ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। अब सोमवार को आने वाला सुप्रीम कोर्ट का फैसला इस हाई-प्रोफाइल मामले में एक महत्वपूर्ण मुकाम हो सकता है, जिससे आगे ट्रायल प्रक्रिया और हिरासत की स्थिति पर दिशा निर्भर करेगी।

300 KM तक मार करेगा रॉकेट, देश की इस डिफेंस कंपनी को सेना से मिला ₹292 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट

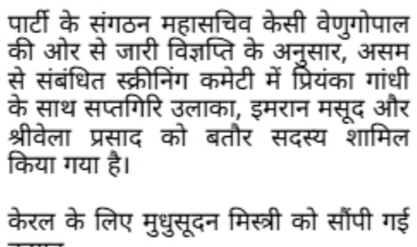

नई दिल्ली: भारतीय सेना अपनी रॉकेट लॉन्चिंग सिस्टम को और मजबूत करने के लिए स्वदेशी डिफेंस कंपनी नाइब लिमिटेड के साथ 292 करोड़ रुपये का एक बड़ा सौदा करने जा रही है। इस सौदे के तहत सेना को ग्राउंड इक्विपमेंट, एक्सेसरीज और खास तरह के रॉकेट मिलेंगे। यह खरीद सेना की लंबी अवधि की योजनाओं का हिस्सा है, जिसका मकसद दुश्मन पर तेजी से और गहराई तक मार करने की क्षमता को बढ़ाना है।

नाइब कंपनी ने बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज को दी गई जानकारी में बताया है कि उन्होंने भारतीय सेना के साथ एक सप्लाई कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। इस कॉन्ट्रैक्ट के तहत नाइब, यूनिवर्सल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम के लिए ग्राउंड इक्विपमेंट, एक्सेसरीज, ईएसपी (इलेक्ट्रॉनिक सपोर्ट मेजर्स) और एम्युनिशन (गोला-बारूद) का निर्माण और सप्लाई करेगी। यह सिस्टम खास इसलिए है क्योंकि यह 150 किलोमीटर और 300 किलोमीटर तक की दूरी पर मार करने वाले अलग-अलग तरह के रॉकेट दाग सकता है। इस पूरे सौदे की कुल कीमत 292.69 करोड़ रुपये है, जिसमें सभी टैक्स शामिल हैं।

नाइब खुद को एक ऐसी डिफेंस प्रोडेक्ट कंपनी बताती है जो भारत को रक्षा उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने के लिए जरूरी सिस्टम और पुर्जे बनाती है। सूत्रों के मुताबिक, यह ऑर्डर इजरायली पल्ससिस्टम के लिए है। खास बात यह है कि यह खरीद 'इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट' (EP) रूट के तहत की जा रही है। इसका मतलब है कि सेना को यह सामान जल्दी चाहिए। कंपनी अगले 12 महीनों के अंदर किश्तों में इस ऑर्डर को पूरा करके सप्लाई करेगी।

इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट (EP) का रास्ता क्यों?
यह इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट (EP) की सुविधा मई 2020 में चीन के साथ हुए एलएसी (Line of Actual Control) के तनाव के बाद शुरू की गई थी। यह सेना को ऐसे हालात में तुरंत हथियार और जरूरी सामान खरीदने की ताकत देती है, जब देश की सुरक्षा को खतरा हो या युद्ध जैसी स्थिति बन रही हो। इसका मुख्य मकसद यह है कि किसी भी ऑपरेशन को सफल बनाने के लिए जरूरी सामानों की खरीद या मरम्मत तेजी से हो सके।

हजारों मामले, सैकड़ों गिरफ्तारियाँ... फिर भी सवाल जिंदा: गौवंश बंदी कानून कहाँ चूक रहा है?

संपादकीय... |

महाराष्ट्र में गौवंश बंदी कानून को लेकर बहस अक्सर भावनाओं में उलझ जाती है, लेकिन सच्चाई यह है कि यह मुद्दा आज आस्था बनाम कानून नहीं, बल्कि कानून बनाम अव्यवस्था की कसौटी बन चुका है। सवाल किसी परंपरा का नहीं, बल्कि इस बात का है कि कानून का अमल किस हद तक निष्पक्ष, प्रभावी और संवैधानिक है।

यदि केवल भावनाओं से हटकर सरकारी आंकड़ों को देखा जाए, तो तस्वीर जितनी सख्त दिखती है, उतनी ही असहज भी।

सरकारी आंकड़े क्या संकेत देते हैं

महाराष्ट्र सरकार ने विधानसभा में दिए गए लिखित उत्तर में जो जानकारी प्रस्तुत की, उसे पीटीआई के माध्यम से Financial Express सहित राष्ट्रीय समाचार पत्रों ने प्रकाशित किया। उसके अनुसार—

> वर्ष 2022 से जून 2025 तक महाराष्ट्र में गौहत्या, गौवंश के अवैध परिवहन और बीफ की बिक्री से जुड़े कुल 2,849 मामले दर्ज किए गए।
इसी अवधि में 4,678 लोगों की गिरफ्तारी हुई
और 1,724 टन बीफ जब्त किया गया।

ये आंकड़े प्रशासनिक सख्ती का प्रमाण हैं, लेकिन साथ ही यह सवाल भी छोड़ जाते हैं कि यदि कार्रवाई इतनी व्यापक है, तो अवैध गतिविधियाँ रुक क्यों नहीं रहीं?

कानून सख्त है, पर वार कहाँ हो रहा है?

नंदुरबार, नासिक, बीड, बुलढाणा, नागपुर और पुणे ग्रामीण जैसे जिलों में लगातार मामले सामने आए। कई जगहों पर संगठित गिरोहों के खिलाफ कड़ी धाराएँ लगाई गईं, यहाँ तक कि मकोका जैसे कठोर कानूनों का भी इस्तेमाल हुआ। इससे यह स्पष्ट है कि राज्य सरकार निष्क्रिय नहीं है।

लेकिन संपादकीय सवाल यह है—
क्या कार्रवाई पूरी आपूर्ति-श्रृंखला पर हो रही है,
या केवल सबसे कमजोर कड़ी पर?

गौवंश के अवैध व्यापार में
➡ बेचने वाला,
➡ ढोने वाला
➡ और खरीदने वाला —
तीनों समान रूप से ज़िम्मेदार हैं।
यदि किसी एक कड़ी पर ही कार्रवाई सीमित रहे और बाकी नेटवर्क सुरक्षित रहे, तो अपराध का चक्र टूटना मुश्किल है। यह जिम्मेदारी किसी समाज की नहीं, बल्कि अपराध से जुड़े हर व्यक्ति की है—चाहे वह किसी भी समुदाय से हो।

जब कानून पीछे और भीड़ आगे आ जाए

यहीं से विषय और संवेदनशील हो जाता है। गौवंश संरक्षण के नाम पर कानून के बाहर जाकर की गई कार्रवाई न केवल गलत है, बल्कि सीधे संविधान के खिलाफ भी है। इस संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट का स्पष्ट निर्देश मौजूद है।

तहसीन पूनावाला बनाम भारत सरकार मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने साफ कहा कि
गौ-रक्षा या किसी भी नाम पर भीड़ द्वारा हिंसा (Mob Lynching) अस्वीकार्य है, और इसे रोकना राज्य सरकार की संवैधानिक जिम्मेदारी है। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि कानून लागू करने का अधिकार केवल राज्य को है, किसी समूह या भीड़ को नहीं।

इस आदेश का महत्व इसलिए भी बढ़ जाता है क्योंकि गौवंश से जुड़े मामलों में यदि कानून की जगह भीड़ हावी हो जाए, तो वह व्यवस्था नहीं, अराजकता कहलाएगी।

केंद्र और राज्य—दोनों की साझा जिम्मेदारी

संविधान का अनुच्छेद 48 पशु संरक्षण की बात करता है, लेकिन अनुच्छेद 21 नागरिक की सुरक्षा और गरिमा की गारंटी देता है। यही संतुलन केंद्र सरकार और राज्य सरकार—दोनों की नीतियों का आधार होना चाहिए। गौवंश संरक्षण कानून तभी टिकाऊ होगा, जब उसका अमल कानूनी, पारदर्शी और मानवीय होगा।

यह स्पष्ट कहा जाना चाहिए कि
कानून का पालन होगा, लेकिन कानून के नाम पर डर या हिंसा नहीं।

संपादकीय निष्कर्ष: आंकड़े उपलब्धि नहीं, चेतावनी हैं

2,849 मामले, 4,678 गिरफ्तारियाँ और 1,724 टन बीफ की जब्ती—
ये आंकड़े सिर्फ प्रशासनिक उपलब्धि नहीं, बल्कि एक चेतावनी भी हैं।

चेतावनी इस बात की कि
✓ केवल गिरफ्तारी से समस्या खत्म नहीं होती
✓ केवल कानून सख्त कर देने से अपराध नहीं रुकता
✓ और सबसे अहम—कानून को भीड़ के हवाले करना लोकतंत्र के लिए घातक है

अब समय है कि महाराष्ट्र प्रशासन

पूरे नेटवर्क पर समान रूप से कार्रवाई करे,

किसी भी समाज को अपराध से न जोड़े,

और सुप्रीम कोर्ट द्वारा तय संवैधानिक मर्यादा को ज़मीनी स्तर पर लागू करे।

क्योंकि अंततः कानून की असली परीक्षा उसकी सख्ती में नहीं, बल्कि उसके न्यायपूर्ण और संतुलित अमल में होती है।

वेनेजुएला में खुद सरकार चलाएगा अमेरिका, मादुरो की गिरफ्तारी के बाद डोनाल्ड ट्रंप का ऐलान

वॉशिंगटन: वेनेजुएला में फिलहाल अमेरिका सत्ता का कामकाज देखेगा। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि जब तक सत्ता का हस्तांतरण नहीं हो जाता, तब तक अमेरिका ही वेनेजुएला को चलाएगा। वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को गिरफ्तार करने के बाद ट्रंप ने ये कहा है। अमेरिका ने शनिवार को हमला करते हुए वेनेजुएला के राष्ट्रपति और उनकी पत्नी को पकड़ लिया है। इससे वेनेजुएला में सत्ता का संकट है। ट्रंप के बयान से साफ है कि वेनेजुएला में अब अमेरिका की कठपुतली सरकार बनेगी।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वेनेजुएला का सफल ऑपरेशन उनके लिए एक चेतावनी होनी चाहिए, जो अमेरिकी संप्रभुता को खतरा पहुंचाते हैं। सबसे जरूरी बात यह है कि वेनेजुएला के सभी तेल पर लगा बैन पूरी तरह से लागू रहेगा। वेनेजुएला के राजनीतिक और सैन्य लोग समझ लें कि मादुरो के साथ जो हुआ, वह उनके साथ भी हो सकता है।

अमेरिका लाए जा रहे मादुरो
डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी कहा है कि वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी को युद्धपोत से अमेरिका लाया जा रहा है, उन पर न्यूयॉर्क में मुकदमा चलेगा। ट्रंप ने यह भी कहा कि वेनेजुएला में अब मादुरो के वफादारों के लिए कोई जगह नहीं है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने वेनेजुएला की ऑइल इंडस्ट्री में कूदने का भी ऐलान किया है।
डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका अब वेनेजुएला के तेल उद्योग में ना सिर्फ दखल देगा बल्कि पूरी मजबूती से शामिल होगा। ट्रंप ने कहा, 'अमेरिकी एनर्जी कंपनियां वेनेजुएला के तेल सेक्टर में बड़ी भूमिका निभाएंगी।

हमारे पास दुनिया की सबसे बड़ी तेल कंपनियां हैं। हम इसमें बहुत बड़े स्तर पर शामिल होने वाले हैं।'अमेरिका की मादुरो से चिढ़
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप काफी समय से वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो पर आरोप लगाते रहे हैं कि वो अमेरिका में मादक पदार्थों की तस्करी और अपराध फैलाने में शामिल हैं। हालिया दिनों में अमेरिका ने कई दफा वेनेजुएला के टैंकरों को निशाना बनाया। इसके बाद शनिवार को अमेरिका ने वेनेजुएला पर हमला कर दिया और मादुरो को पकड़ लिया।

अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने अपने बयान में कहा है कि ट्रंप प्रशासन ने मादुरो को बार-बार चेतावनी दी थी। हमने साफ किया था कि ड्रग तस्करी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हमारा रुख साफ है कि ड्रग तस्करी बंद होनी चाहिए और चोरी का तेल अमेरिका को वापस किया जाना चाहिए। हमने इसके लिए कड़े कदम उठाए हैं।

WORLD NEWS | राष्ट्रपति और अब अमेरिका के कैदी

निकोलस मादुरो: बस ड्राइवर से वेनेजुएला के ताकतवर राष्ट्रपति और अब अमेरिका के कैदी

NEWS AGENCY

कारकास: अमेरिकी आर्मी ने शनिवार तड़के वेनेजुएला पर बड़े पैमाने पर हमला किया। इसी हमले के दौरान अमेरिकी सेना ने वेनेजुएला निकोलस मादुरो और उनकी बीवी सिलिया फ्लोरेस पत्नी को पकड़ लिया। दोनो को उनके घर से पकड़ने के बाद एक युद्धपोत के जरिए अमेरिका लाया जा रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मादुरो की तस्वीर शेयर की है, जिसमें एक कैदी के तौर पर उनके आंखों पर पट्टी बंधी हुई है। कुछ घंटे पहले तक वेनेजुएला के राष्ट्रपति रहे निकोलस मादुरो की यह तस्वीर उनके समर्थकों के लिए दिल तोड़ने वाली हो सकती है। मादुरो की जिंदगी को देखा जाए तो वह फर्श से अर्श तक पहुंचे और अब एक झटके में अर्श से फर्श पर हैं। बस ड्राइवर से वेनेजुएला के राष्ट्रपति बनने और ट्रंप को चुनौती देने वाले मादुरो आज अमेरिका के कैदी हैं।

निकोलस मदुरो का जन्म नवंबर, 1962 को एक मजदूर परिवार में हुआ था। उनके पिता एक ट्रेड यूनियन लीडर रहे। मादुरो ने 1990 के दशक की शुरुआत में एक बस ड्राइवर के तौर पर काम किया था। इसी दौरान 1992 में सेना अधिकारी ह्यूगो शावेज ने तख्तापलट की नाकाम कोशिश की थी। मदुरो ने तब नौकरी छोड़ दी और शावेज को जेल से रिहा कराने के लिए कैंपेन किया। वह उनके वामपंथी राजनीतिक प्रोजेक्ट के पक्के समर्थक के तौर पर उभरे।

1998 में राजनीति में एंट्री
मादुरो ने अपने देश में राजनीति करने से पहले 1986 में एक साल के वैचारिक प्रशिक्षण के लिए क्यूबा गए थे। यह हाई स्कूल के बाद उनकी एकमात्र औपचारिक शिक्षा थी।

राष्ट्रपति और अब अमेरिका के कैदी

साल 1998 में शावेज राष्ट्रपति बने तो मादुरो ने राजनीति में कदम रखा और विधायिका के सदस्य बने। वह नेशनल असेंबली के अध्यक्ष बने और बाद में विदेश मंत्री के रूप में काम किया। मादुरो देश के उपराष्ट्रपति भी रहे। वह शावेज के समय देश के बेहद ताकतवर शख्स बन चुके थे। मादुरो ने वेनेजुएला के तेल धन से समर्थित अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन बनाने के लिए बड़े पैमाने पर यात्राएं कीं और अपनी राजनीतिक स्थिति को मजबूत किया। इसी के चलते शावेज ने अपनी मौत से पहले सार्वजनिक रूप से मादुरो को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था। वर्ष 2013 में अपने निधन से पहले राष्ट्र को दिए गए अपने अंतिम संबोधन में शावेज ने मादुरो को अपना उत्तराधिकारी कहा था। ऐसे में शावेज की मौत के बाद मादुरो 2013 में राष्ट्रपति बन गए। इसके बाद से मादुरो लगातार इस पद पर बने हुए थे। अमेरिका के कैदी बनने के बाद अब उनका भविष्य संकट में है।

'धुरंधर' में भारत सरकार ने किया ऐसा बदलाव कि बलूच नेता दे रहे धन्यवाद, बोले- दिल जीत लिया

NEWS AGENCY

इस्लामाबाद: बीते साल की सबसे बड़ी हिट फिल्मों में शुमार 'धुरंधर' में कुछ छोटे बदलाव किए गए हैं। नए साल यानी 1 जनवरी से सिनेमाघरों में धुरंधर देखने वालों को बलूच शब्द सुनने को नहीं मिलेगा। इस फैसले का बलूचिस्तान के अलगाववादी नेता मीर यार बलूच ने स्वागत किया है। लंबे समय से बलूचिस्तान को पाकिस्तान से आजाद कर अलग देश बनाने की मांग कर रहे मीर यार ने कहा है कि हम इस फैसले के लिए भारत सरकार का आभार जताते हैं।

मीर ने अपने ट्वीट में लिखा है, 'रिपब्लिक ऑफ बलूचिस्तान के लोग भारत सरकार के सूचना-प्रसारण मंत्रालय को दिल से धन्यवाद देते हैं। हम खुले दिल से पिछले साल 5 दिसंबर को रिलीज हुई धुरंधर फिल्म से बलूच शब्द को म्यूट करने के फैसले की तारीफ करते हैं। फिल्म में बलूच शब्द को ऐसे संदर्भ में इस्तेमाल किया गया था, जिसका नकारात्मक संदेश जा रहा था।'

बलूचों का दिल जीत लिया: मीर
मीर यार ने आगे लिखा कि फिल्म में जिस तरह से बलूच शब्द का गलत तरीके से इस्तेमाल हुआ, उस पर दुनियाभर के बलूच समुदाय ने कड़ी आपत्ति जताई थी। भारत सरकार ने बलूचों की इस भावना को समझा है। इस समझदार और संवेदनशील कदम ने दुनियाभर के बलूच लोगों का दिल जीत लिया है। यह बलूचों की पहचान और भावनाओं के प्रति सम्मान को दिखाता है।

1 जनवरी से फिल्म 'धुरंधर' थिएटर्स में कुछ बदलावों के साथ दिखाई जा रही है। इसमें 'बलोच' शब्द को म्यूट करना शामिल है।

इस फिल्म की कहानी पाकिस्तान की राजनीति, कराची के गैंगवार, बलूचों के मुद्दों और भारतीय खुफिया एजेंसी की गुप्त कार्रवाइयों पर आधारित है। इसमें अक्षय खन्ना, संजय दत्त और रणवीर सिंह जैसे बड़े फिल्मी सितारों ने काम किया है।
फिल्म में बलूचों के बारे नकारात्मकता की बात कुछ सोशल यूजर्स की ओर से उठाई गई थी। हालांकि बदलाव के पीछे ये नहीं बताया गया है कि क्यों यह फैसला लिया गया है। 31 दिसंबर को वितरकों ने सभी थिएटर्स को ईमेल भेजकर फिल्म की डिजिटल कॉपी (डीसीपी) बदलने की सूचना दी। फिल्म में दो शब्दों को म्यूट किया गया है और एक डायलॉग बदला गया है।

महाराष्ट्र विशेष

कोकण > पश्चिम महाराष्ट्र > मराठवाड़ा > विदर्भ

नंदिग्राम टाईम्स

Sunday 4th January 2026 वर्ष - 9 , अंक 249 , पृष्ठ 03

किसी ने गलत इरादे से मुस्लिम महिलाओं को छुआ तो हाथ काट दूंगा, ओवैसी के नेता इम्तियाज जलील ने दी चेतावनी

जालना (महाराष्ट्र): हिजाब विवाद की गर्माहट के बीच एआईएमआईएम (AIMIM) के नेता और पूर्व सांसद इम्तियाज जलील ने एक बेहद विवादित बयान दिया है, जिसने राजनीतिक और सामाजिक हलकों में खूब चर्चा पैदा कर दी है। जलील ने महाराष्ट्र के जालना में एक जनसभा को संबोधित करते हुए चेतावनी दी कि यदि कोई भी व्यक्ति गलत इरादे से मुस्लिम महिलाओं को छूने की हिम्मत करेगा, तो वह उसका हाथ काट दूंगा।

यह बयान हिजाब विवाद से जुड़े गतिरोध के बीच आया है, जो तब शुरू हुआ जब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक सार्वजनिक कार्यक्रम में एक मुस्लिम महिला का हिजाब हाथ से हटाया था। इस घटना के बाद उत्तर प्रदेश के एक मंत्री की टिप्पणी ने विवाद को और भड़का दिया था।

जलील ने अपने भाषण में कहा कि यह चेतावनी मुस्लिम महिलाओं के सम्मान और सुरक्षा की रक्षा के लिए है। उन्होंने आरोप लगाया कि “तथाकथित धर्मनिरपेक्ष दल” गुंडों और आपराधिक तत्वों का समर्थन करते हैं, लेकिन **मुस्लिम समुदाय के पक्ष में खड़े होने में हिचकते हैं।”

उन्होंने हिजाब विवाद को लेकर नीतीश कुमार को सीधे तौर पर निशाने पर लिया और कहा कि इस तरह के घटनाओं को राजनीतिक बयानबाजी में उल्टा-सीधा गलत संदेश दिया जा रहा है। जलील का यह बयान 15 जनवरी को होने वाले जालना नगर निगम चुनावों के लिए AIMIM के 17 उम्मीदवारों के समर्थन में प्रचार के दौरान आया था।

राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार, जलील का बयान न केवल सामाजिक रूप से संवेदनशील है, बल्कि यह चुनावी माहौल को और अधिक तनावपूर्ण भी बना सकता है, खासकर तब जब हिजाब और धार्मिक पहचान का मुद्दा पूरे देश में तेज़ी से बहस का केंद्र बना हुआ है। इस बयान पर विभिन्न संगठनों और नेताओं की प्रतिक्रियाएँ भी आनी शुरू हो गई हैं, जिनमें कुछ ने इसे अत्यधिक और अनुचित बताया है, जबकि कुछ समर्थकों ने इसे मुस्लिम महिलाओं के सम्मान की रक्षा के लिए वाजिब चेतावनी भी कहा है। वर्तमान में यह विवाद सामाजिक और राजनीतिक मंचों पर एक गरम विषय बना हुआ है।

BMC ELECTION 2026 | मुंबई का मेयर मराठी-हिंदू होगा

मैं छाती ठोककर बोलता हूं, मुंबई का मेयर मराठी-हिंदू होगा, BJP-शिवसेना की रैली में गरजे सीएम फडणवीस

मुंबई: बृहन्मुंबई महानगरपालिका (BMC) चुनाव 2026 के मद्देनजर भाजपा और एकनाथ शिंदे नेतृत्व वाली शिवसेना (महायुति गठबंधन) ने एक संयुक्त रैली का आयोजन किया, जिसमें मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने ठाकरे-गुट को कड़ा राजनीतिक निशाना साधा और अपना चुनावी एजेंडा जनता के बीच रखा।

वर्ली के NSCI डोम में आयोजित संयुक्त रैली में सीएम फडणवीस ने कहा कि BMC चुनाव मुंबई की छवि बदलने और नागरिकों के जीवन को बेहतर बनाने का अवसर है। उन्होंने आरोप लगाया कि बाकी राजनीतिक दल सिर्फ खाली वादों और भावनात्मक राजनीति में उलझे हैं, जबकि महायुति गठबंधन विकास, सुशासन और जनहित के एजेंडे पर केंद्रित है। फडणवीस ने यह भी जोर देकर कहा कि

मुंबई का अगला मेयर मराठी और हिंदू ही होगा — यह बयान अभिव्यक्ति और पहचान के मुद्दे को चुनावी राजनीति का हिस्सा बनाता है। उन्होंने यह घोषणा करते हुए कहा कि महायुति गठबंधन की प्राथमिकता स्थानीय संस्कृति और पहचान के साथ-साथ प्रशासन की सशक्तता भी है।

एकनाथ शिंदे ने भी रैली में ठाकरों पर निशाना साधा और कहा कि उनके प्रतिद्वंद्वी मराठी अस्मिता के नाम पर सिर्फ राजनीतिक भावनाओं को भड़का रहे हैं, जबकि वास्तविक कार्य और विकास परियोजनाओं पर महायुति ध्यान दे रही है।

शिंदे ने कहा कि शहर के लिए जो पेशकश की जा रही है, वह स्थायी और सर्वांगीण प्रगति की दिशा में है। दोनों नेताओं ने जनता से बीएमसी में महायुति के पक्ष में मतदान करने की अपील की, जिसमें बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर, यातायात, स्वच्छता, स्वास्थ्य सुविधाएँ और मुंबई को और अधिक सुरक्षित और रहने योग्य बनाने के वादों को प्रमुखता दी गई।

राजनीय विश्लेषक मानते हैं कि इस चुनाव में मराठी-हिंदू पहचान, विकास एजेंडा और लोकल हितों को लेकर चुनावी युद्ध काफी तीव्र होगा, जिसमें सभी प्रमुख दल अपने-अपने चुनावी संदेश को जोरशोर से पेश कर रहे हैं।

बीएमसी चुनावों की तिथि 15 जनवरी 2026 है, जिसके लिए सभी पार्टियां पूरी ताकत से प्रचार में जुटी हैं और अगले कुछ हफ्तों में राजनीतिक घमासान और भी तेज होने की संभावना है।

डिलीवरी के लिए 6KM पैदल चली गर्भवती महिला, ब्लड प्रेशर बढ़ने से मौत, महाराष्ट्र में सामने आई शर्मनाक घटना

गढ़चिरोली (महाराष्ट्र): महाराष्ट्र के जंगली और दूरदराज इलाकों में स्वास्थ्य बुनियादी सुविधाओं की कमी एक बार फिर जानलेवा साबित हुई है। जिले के एटापल्ली तालुका में रहने वाली 24 वर्षीय आशा संतोष किरंगा, जो अपनी नौवीं महीने की गर्भवती थी, को डिलीवरी के लिए कोई स्थानीय अस्पताल या वाहन सुविधा न मिलने के कारण लगभग 6 किलोमीटर पैदल चलना पड़ा। उनके गांव आलदंडी टोला से मुख्य सड़क तक कोई उचित रास्ता या वाहन सेवा उपलब्ध नहीं थी, जिससे उन्हें जंगल के रास्ते से अपनी बहन के घर पेठा तक जाना पड़ा।

1 जनवरी की सुबह इस दर्दनाक यात्रा के बाद अगले दिन 2 जनवरी को उन्हें गंभीर प्रसव वेदना हुई। भारी कठिनाई के बीच उन्हें हेडरी स्थित काली अम्माल अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने सिजेरियन ऑपरेशन का निर्णय लिया, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी और गर्भ में बच्चा पहले ही मृत हो चुका था। उच्च रक्तचाप (ब्लड प्रेशर) के कारण महिला की हालत तेजी से बिगड़ी और उसकी मौत हो गई।

गढ़चिरोली जिला मुख्य रूप से जंगलों और पहाड़ों से घिरा है, और यहां सड़क तथा प्रसव सुविधा जैसी बुनियादी चिकित्सा सेवाएँ नहीं होने के कारण यह घटना सामने आई है। स्थानीय स्वास्थ्य अधिकारियों ने बताया कि महिला आशा कार्यकर्ता थी और उसे ASHA स्वास्थ्य कर्मियों द्वारा पंजीकृत किया गया था, लेकिन इमरजेंसी के समय आवश्यक सुविधाओं का अभाव उसकी जान लेने का कारण बन गया। घटना ने स्वास्थ्य सेवाओं और आधारभूत ढांचे की कमी पर गंभीर सवाल उठाए हैं, खासकर उन इलाकों में जहां दूर-दराज के गांवों के लोग इलाज के लिए जोखिम भरे सफर करने को मजबूर होते हैं। स्थानीय लोगों और स्वास्थ्य अधिकारियों के बीच अब इस दुखद घड़ी पर आलोचना और चिंता दोनों बढ़ रही हैं।

ठाणे: छात्राओं का प्रेगनेंसी टेस्ट शर्मनाक, स्कूल में दूसरे सुसाइड के बाद पहुंची रुपाली चाकणकर, जांच में पकड़ी खामी

मुंबई/ठाणे: महाराष्ट्र के सरकारी आवासीय स्कूलों में छुट्टी से लौटने के बाद छात्राओं की प्रेगनेंसी टेस्ट को महिला आयोग की चेयरपर्सन रुपाली चाकणकर शर्मनाक करार दिया है। शुक्रवार को ठाणे के सरकारी आवासीय विद्यालय में 16 साल की आदिवासी छात्रा की कथित आत्महत्या के बाद पहुंची चाकणकर ने बातचीत में दावा किया कि छुट्टियों के बाद स्कूल लौटने वाली छात्राओं को गर्भावस्था जांच के लिए मजबूर किया गया। उन्होंने कहा कि इस तरह की जांच शर्मनाक हैं। यह कृत्य लड़कियों के आत्मसम्मान और आत्मविश्वास को तोड़ता है। चाकणकर ने कहा कि महिला आयोग ने आदिवासी विकास विभाग को इस तरह के परीक्षण को तत्काल बंद करने का निर्देश दिया है। महिला आयोग की अध्यक्षा की प्रारंभिक जांच में संस्थान में गंभीर लापरवाहियां सामने आईं।

स्कूल में पकड़ी गंभीर खामी

महाराष्ट्र राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष रुपाली चाकणकर शुक्रवार को ठाणे जिले की मुरबाड तहसील के मोरोशी स्थित उस स्कूल का दौरा किया, जहां 25 दिसंबर को 10वीं कक्षा की एक छात्रा ने फंदा लगाकर कथित तौर पर आत्महत्या कर ली थी। इस मामले में यौन उत्पीड़न और आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में 17 वर्षीय एक लड़के को भारतीय न्याय संहिता और यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम के प्रासंगिक प्रावधानों के तहत हिरासत में लिया गया। कुछ अभिभावकों ने हाल में स्कूल में अत्यधिक कठोर अनुशासन को लेकर शिकायतें की थीं। चाकणकर ने एक गंभीर सुरक्षा चूक पर भी प्रकाश डाला। इसमें नजदीकी रिश्तेदार के रूप में सूचीबद्ध नहीं किए गए व्यक्तियों को छुट्टियों के दौरान लड़कियों को घर ले जाने की कथित तौर पर अनुमति दी गई।

स्कूल के काम की निगरानी होगी

चाकणकर ने कहा कि कम समय में इस संस्था में आत्महत्या का दूसरा मामला है। हमने आदेश दिए हैं कि सोमवार से स्कूल के पूरे कामकाज की व्यापक जांच की जाए। इस बीच, कठोर अनुशासन के आरोपों के बाद स्कूल के प्रधानाचार्य प्रह्लाद भोई और वार्डन जयश्री वाघधे को निलंबित कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि पूरे तंत्र को पारदर्शी बनना होगा। हमने स्कूल प्रशासन को छात्राओं को तत्काल परामर्श उपलब्ध कराने और मानसिक दबाव के किसी भी संकेत पर नजर रखने के लिए अभिभावकों के साथ नियमित संवाद बनाए रखने का निर्देश दिया है।

BMC चुनाव: आदित्य और अमित ठाकरे ने किया मनसे-यूबीटी के घोषणापत्र को फाइनल, मुफ्त की सौगातों पर खेला दांव

संवाददाता

मुंबई: आगामी बीएमसी (बृहन्मुंबई महानगरपालिका) चुनाव 2026 के लिए शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे)-मनसे (यूबीटी-MNS) गठबंधन ने अपना साझा घोषणापत्र अंतिम रूप दे दिया है। आदित्य ठाकरे और अमित ठाकरे ने गठबंधन के 16-सूत्रीय चुनावी वचननामे की रूपरेखा तैयार की है, जिसमें विकास-और जनहित आधारित मुफ्त सुविधाओं को मुख्य आकर्षण बनाया गया है।

घोषणापत्र में मुंबई के नागरिकों के लिए कई लोकलुभावन वादे शामिल हैं। इसमें महिलाओं को प्रतिमाह ₹1,500 वित्तीय सहायता, घरों के 700 वर्ग फुट तक की संपत्ति पर टैक्स माफी, तथा हर युवा के लिए ₹1 लाख का फंड देने का वादा शामिल है, जिससे वे बिजनेस, शिक्षा या कौशल विकास में निवेश कर सकें।

मुंबई में BEST द्वारा 100 यूनिट तक मुफ्त बिजली, पेयजल और परिवहन में राहत, तथा सुस्त दरों पर नाश्ता-खाना जैसी योजनाएँ भी प्रस्तावित हैं। शहर भर में ‘मासाहब किचन’ के तहत नाश्ता-दोपहर का भोजन ₹10 में देने का प्रस्ताव है। इसके अलावा बीएमसी-अस्वास्थ्य केंद्रों में नए मेडिकल कॉलेज, 24×7 हेल्थ कंट्रोल रूम, तथा कैंसर अस्पताल की स्थापना का वादा भी किया गया है।

घोषणापत्र में यह भी शामिल है कि मिल मजदूरों, BEST कर्मचारियों और पुलिस कर्मियों के लिए लगभग 1 लाख आवास बनाया जाएगा और ग़रीब-मझोले वर्ग के लिए आवास नीति में सुधार किया जाएगा। इसके अलावा पुरानी इमारतों के पुनर्विकास नियमों में बदलाव करके प्रत्येक फ्लैट के लिए पार्किंग की सुनिश्चित जगह का प्रावधान भी किया जाएगा। राजनीति विश्लेषकों के अनुसार यह घोषणापत्र लोकलुभावन वादों और मुफ्त योजनाओं के ज़रिए मतदाताओं को आकर्षित करने की रणनीति का हिस्सा है, जिससे बीएमसी में गठबंधन को मजबूत प्रदर्शन दिलाने की कोशिश की जा रही है। आगामी मतदान 15 जनवरी 2026 को निर्धारित है और घोषणापत्र को प्रचार के मुख्य आधार के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है।

बीएमसी चुनाव 2026: दहिसर वार्ड 2 में तेजस्वी घोसालकर बनाम धनश्री कोलगे

मुंबई: आगामी बीएमसी चुनाव 2026 में दहिसर वार्ड नंबर 2 का मुकाबला हाई-प्रोफाइल है। भाजपा ने तेजस्वी घोसालकर को मैदान में उतारा है, जबकि शिवसेना (UBT) ने धनश्री कोलगे को उम्मीदवार बनाया है। दोनों पहले एक ही पार्टी से जुड़े थे, अब प्रतिद्वंद्वी हैं।

यह मुकाबला भाजपा और शिवसेना (UBT) के बीच राजनीतिक समीकरण की जंग भी है। स्थानीय पहचान, पारिवारिक संबंध और पार्टी नीतियों के आधार पर मतदाता अपने फैसले देंगे। मतदान 15 जनवरी 2026 को होगा और नतीजे पूरे मुंबई के चुनाव परिणाम को प्रभावित कर सकते हैं।

महायुति को छोड़कर चाचा के पास लौट आएं अजित, NCP-बीजेपी के आमने-सामने आने पर राउत ने फेंकी गुगली

Reporter Name

मुंबई: महाराष्ट्र की राजनीति में शिवसेना (UBT) नेता संजय राउत ने राष्ट्रीय काँग्रेस पार्टी (NCP) के बंटे हुए गुट को फिर से एकजुट करने की अपील करते हुए अजित पवार से भाजपा-नेतृत महायुति गठबंधन छोड़कर अपने चाचा शरद पवार के नेतृत्व वाले NCP (SP) में लौट आने का आग्रह किया है। राउत ने कहा है कि पुणे और पिंपरी-चिंचवड नगर निकाय चुनावों में दोनों NCP गुटों ने भाजपा के खिलाफ मिलकर चुनाव लड़ने का फैसलों किया है, इसलिए अब समय आ गया है कि वे एक ही पार्टी में वापस आएं और विभाजन खत्म करें।

राउत ने सवाल उठाया कि भाजपा के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप लगाने वाले अजित पवार आज उसी महायुति सरकार का हिस्सा क्यों हैं।

उन्होंने कहा कि अगर पवार के राजनीतिक रुख में बदलाव आया है, तो उन्हें भाजपा-नेतृत सरकार को छोड़कर शरद पवार के नेतृत्व वाली असल NCP के साथ विलय कर लेना चाहिए।

राष्ट्रीय राजनीति में 2023 में NCP का विभाजन हुआ था जब अजित पवार और कुछ अन्य विधायकों ने भाजपा-शिंदे सरकार में शामिल होकर अलग NCP गुट बनाया था, जिसे बाद में चुनाव आयोग ने आधिकारिक NCP मान्यता और पार्टी का मूल “घड़ी” चिन्ह प्रदान किया था। राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार, राउत का यह बयान महाराष्ट्र के नगर निगम चुनावों के संदर्भ में विपक्षी दलों में एकता के प्रयास के रूप में देखा जा रहा है। महाराष्ट्र में 15 जनवरी को होने वाले नगर निकाय चुनावों में भाजपा-नेता महायुति और विपक्षी गुटों के बीच कड़ी प्रतिस्पर्धा होने की संभावना है, जिसमें NCP के विभाजन के कारण राजनीतिक समीकरण बेहद संवेदनशील बन गए हैं। राउत का यह आग्रह न केवल राजनीतिक रणनीति और गठबंधन स्थिरता से संबंधित है, बल्कि महाराष्ट्र के राजनीतिक परिदृश्य में पुराने सहयोग और जातीय-ओर पार्टी पहचान को पुनर्जीवित करने का भी प्रयास माना जा रहा है।

महाराष्ट्र के नए डीजीपी पर क्यों है सभी को नाज? मुंबई 26/11 से लेकर पहलगाम हमले तक खोदी आतंकियों की कब्र

मुंबई: वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी सदानंद वसंत दाते को महाराष्ट्र का नया पुलिस महानिदेशक (DGP) नियुक्त किया गया है, जो अपने उत्कृष्ट सेवा रिकॉर्ड और आतंकवाद-रोधी अभियानों के लिए पूरे देश में सम्मानित हैं। दाते ने 26/11 मुंबई आतंकी हमलों के दौरान बहादुरी का परिचय देते हुए आतंकियों का मुकाबला किया था और बाद में उन्हें प्रेसिडेंट पुलिस मेडल फॉर गैलेंट्री से भी सम्मानित किया गया था।

59 वर्षीय दाते 1990 बैच के IPS अधिकारी हैं और उन्होंने हाल तक नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी (NIA) के प्रमुख के रूप में देशभर में गंभीर मामलों की जांच का नेतृत्व किया। उनके नेतृत्व में NIA ने 26/11 हमले से जुड़े प्रमुख संदिग्ध तहव्वुर राणा के प्रत्यर्पण की प्रक्रिया में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिससे भारत को आतंकी साजिश के और कई उत्तर मिल सकें।

दाते ने न केवल मुंबई पुलिस में अतिरिक्त आयुक्त (सेंट्रल रीजन) के रूप में आतंकवादियों से मुठभेड़ों का सामना किया, बल्कि महाराष्ट्र एंटी-टेरेरिज्म स्क्वॉड (ATS) के प्रमुख, CBI में DIG, और CRPF में IG (ऑपरेशन) जैसे महत्वपूर्ण पदों पर भी कार्य किया है।

उनकी लंबी सेवा में उन्होंने पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले जैसी गंभीर घटनाओं की जांच भी संभाली है और आतंकवाद विरोधी अभियानों में अपनी नेतृत्व क्षमता का लोहा मनवाया है।

अब दाते लगभग दो लाख कर्मियों वाली महाराष्ट्र पुलिस का नेतृत्व करेंगे और उन्हें राज्य की कानून-व्यवस्था और सुरक्षा रणनीति को और मजबूत बनाने की जिम्मेदारी दी गई है। महाराष्ट्र सरकार और पुलिस विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों ने उनकी नियुक्ति की व्यापक सराहना की है, जिसे राज्य में सुरक्षा और न्याय को सुदृढ़ करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया जा रहा है।

नांदेड़ वॉक्स

नांदेड़ जिला > नांदेड़ शहर

नंदिग्राम टाईम्स

Sunday 4th January 2026 वर्ष - 9 , अंक 249 , पृष्ठ 04

नांदेड में विधायक कल्याणकर को विरोध का भारी सामना, उपमुख्यमंत्री के करीबियों के टिकट काटे गए

नांदेड (महाराष्ट्र): नांदेड-वाघाळा महानगरपालिका चुनाव के तहत एक बड़े राजनीतिक उलटफेर में शिंदे शिवसेना के करीबी गजानन पाटील की पत्नी मीनल पाटील की उमेदवारी काट दी गई, जिसका श्रेय स्थानीय शिवसेना विधायक बालाजीराव कल्याणकर के लगातार विरोध को दिया जा रहा है। पाटील का टिकट कटा जाना चुनावी रणभूमि में एक बड़ा राजनीतिक संदेश माना जा रहा है।

गजानन पाटील लंबे समय से उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और सांसद श्रीकांत शिंदे के करीब रहे हैं और शिंदे के कार्यकाल में उन्होंने आपले सरकार जनकल्याण कक्ष के प्रमुख के रूप में कार्य किया था। इसके बाद वे नांदेड में टिकट पाने की उम्मीद में सक्रिय रहे और पिछले छह-आठ महीनों से प्रचार में लगे थे, लेकिन अंततः पार्टी ने उनका टिकट काट दिया। शिंदे शिवसेना के टिकटों का निर्धारण स्थानीय विधायक को अधिकार देकर किया गया और कल्याणकर ने अपने भरोसेमंद कार्यकर्ते श्याम कोकाटे की पत्नी करुणा कोकाटे को उस प्रभाग से उम्मीदवार बनाया है जहाँ पहले पाटील की उम्मीदवारी थी। ऐसे में स्थानीय कार्यकर्ताओं को भी मौका देकर पार्टी के भूमि-स्तर पर समर्थन को मजबूत करने की कोशिश की गई है।

पाटील के लिए हेमंत पाटील सहित अन्य नेताओं ने मध्यस्थता के प्रयास किए, लेकिन स्थानीय विधायक के विरोध ने उन प्रयासों को विफल कर दिया। इससे यह स्पष्ट संकेत मिलता है कि नांदेड में स्थानीय राजनीतिक समीकरणों का चुनावी टिकट वितरण में निर्णायक प्रभाव रहा है। यह घटना उस समय सामने आई है जब नांदेड-वाघाळा महानगरपालिका के 81 सीटों के लिए कुल 491 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं और राजनीतिक हलचल तेज़ है। जगह-जगह से उम्मीदवारों की माघार और टिकटों में बदलाव की खबरें मिल रही हैं, जिससे स्थानीय चुनाव प्रचार और रणनीति दोनों पर प्रभाव पड़ा है।

राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार, यह टिकट काटने का कदम स्थानीय कार्यकर्ताओं और विधायक के दबाव को दर्शाता है तथा यह बताता है कि चुनावी टिकट वितरण में स्थानीय नेतृत्व की अहम भूमिका रहती है।

नांदेड में शिंदे गुट को बड़ा झटका, ऐन वक्त पर दो उम्मीदवारों ने नामांकन वापस लिया — विधायक कल्याणकर भाजपा से नाराज़

नांदेड (महाराष्ट्र): नांदेड-वाघाळा महानगरपालिका चुनाव 2026 के नामांकन वापस करने के अंतिम दिन राजनीतिक घटनाक्रम ने नया मोड़ ले लिया। शिंदे शिवसेना को अप्रत्याशित झटका तब लगा, जब उसके दो अधिकृत उम्मीदवार — महेंद्र पिंपळे (प्रभाग 5A) और वंदना जाधव (प्रभाग 10B) — ने ऐन वक्त पर अपने नामांकन वापस ले लिए। इस कदम से पार्टी के स्थानीय चुनावी समीकरण में बड़ा बदलाव आया और राजनीतिक हलकों में हलचल मच गई।

महेंद्र पिंपळे हाल ही में भाजपा छोड़कर शिंदे सेना में शामिल हुए थे और उन्हें 'एबी-फॉर्म' के तहत प्रभाग 5 से उम्मीदवार बनाया गया था। लेकिन उन्होंने अचानक अपना नामांकन वापस लेते हुए कहा कि अब वे कांग्रेस सांसद अशोकराव चव्हाण के नेतृत्व में काम करेंगे और उनके गुट के साथ जुड़ना चाहते हैं। वहीं, प्रभाग 10B से वंदना जाधव की भी अचानक माघार ने शिंदे सेना के लिए राजनीतिक चुनौती खड़ी कर दी।

इस पर विधायक बालाजी कल्याणकर ने भाजपा पर आरोप लगाया कि उनके उम्मीदवारों के "पलटने" के कारण स्थिति उत्पन्न हुई। शिंदे सेना ने तुरंत दोनों स्थानों पर नए उम्मीदवारों को नामित किया, लेकिन पार्टी की रणनीति और चुनावी तैयारी पर असर पड़ा है।

चुनावी प्रक्रिया के आंकड़ों के अनुसार कुल 1203 नामांकन दाखिल किए गए, जिनमें से 59 अर्ज़ बाद कर दिए गए और 878 अर्ज़ वैध ठहराए गए। माघार लेने की अंतिम तिथि तक 376 उम्मीदवारों ने अपने नामांकन वापस ले लिए, जिससे अब 491 उम्मीदवार चुनावी मैदान में बने हुए हैं।

राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि पिंपळे और जाधव की माघार से स्थानीय राजनीतिक समीकरण और गठबंधन रणनीति प्रभावित होगी। भाजपा को प्रभाग 5 में बढ़त मिलने की संभावना है, जबकि शिंदे सेना को नए उम्मीदवार के साथ अपनी रणनीति बदलनी पड़ेगी।

इस बदलाव से यह स्पष्ट होता है कि नांदेड-वाघाळा महापालिका चुनावों में स्थानीय नेतृत्व, प्रत्याशियों के फैसले और गठबंधन समीकरण निर्णायक भूमिका निभा सकते हैं।

स्थानीय राजनीतिक हलकों में यह चर्चा भी है कि पिंपळे के फैसले में अशोकराव चव्हाण के नेतृत्व और भाजपा के रणनीतिक प्रयासों का विशेष प्रभाव रहा। इस राजनीतिक मोड़ से नांदेड की चुनावी राजनीति में आगामी दिनों में और हलचल की संभावना बनी हुई है, जिससे आगामी मुकाबले और अधिक प्रतिस्पर्धात्मक और रोचक बने हैं।

मुख्य बिंदु:

*शिंदे सेना के दो अधिकृत उम्मीदवारों ने ऐन वक्त पर नामांकन वापस लिया।

*महेंद्र पिंपळे ने भाजपा छोड़कर शिंदे सेना में शामिल होने के बाद भी वापस ले ली और चव्हाण के नेतृत्व में काम करने की घोषणा की।

विधायक कल्याणकर ने भाजपा पर आरोप लगाए कि उनके उम्मीदवारों के कदम ने स्थिति को प्रभावित किया।

कुल 1203 नामांकन में से 376 उम्मीदवारों ने वापस ली, 491 उम्मीदवार मैदान में हैं।

राजनीतिक समीकरण और गठबंधन रणनीति में बदलाव से नांदेड की चुनावी हलचल बढ़ी।

नांदेड में शेतकर्मियों का हृदयद्रावक विरोध — 'शक्तीपीठ महामार्ग' रद्द करो, नहीं तो सामूहिक मृत्यु की अनुमति दो

महाराष्ट्र के नांदेड जिले के अर्धापुर और मालेगांव क्षेत्र के किसानों ने प्रस्तावित नागपुर–गोवा शक्तिपीठ महामार्ग परियोजना के खिलाफ अनोखा विरोध प्रदर्शन किया है। किसानों ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को अपना ज्ञापन उनके ही रक्त से लिखा और जिल्हाधिकारी के माध्यम से सौंपा। ज्ञापन में उन्होंने मांग की है कि या तो यह परियोजना पूरी तरह रद्द की जाए या उन्हें सामूहिक रूप से "इच्छामृत्यु" की अनुमति दी जाए।

किसानों का कहना है कि प्रस्तावित मार्ग की संरेखण योजना उनकी उर्वर और सिंचित कृषि भूमि पर भारी नुकसान पहुंचाएगी, जहां केला, हल्दी जैसी फसलें उगाई जाती हैं और जिनका निर्यात विदेशों में होता है। यह भूमि अप्पर और लोअर पेनगंगा सिंचाई परियोजना के लाभक्षेत्र में भी आती है।

ज्ञापन में 200 से अधिक किसानों के हस्ताक्षर हैं, जिसमें विरोध समिति के संयोजक सुभाष मोरलवार और सतीश कुलकर्णी भी शामिल हैं। उन्होंने चेतावनी दी है कि उनकी मांगों पर त्वरित कार्रवाई नहीं हुई, तो आंदोलन और तीव्र किया जाएगा।

किसानों का यह विरोध अनोखे ढंग का है और राजस्थान, उत्तर भारत समेत अन्य स्थानों पर सरकारी नीतियों के खिलाफ खून से लिखे गए पत्रों की श्रृंखला में शामिल है। पिछले दिनों नर्सिंग कर्मियों ने भी इसी तरह का प्रदर्शन किया था।

महावितरण का सख्त निर्देश: नांदेड-परभणी के 40 गावों में बिजली बकाया तुरंत भरें नहीं तो वसूली कार्रवाई तेज़

नांदेड/हिंगोली : महावितरण ने नांदेड, परभणी और हिंगोली जिलों में बिजली बिलों की भारी थकबाकी के चलते सख्त रुख अपनाया है और 40 गांवों को वसूली के लिये विशेष लक्ष्य के रूप में चिन्हित किया है। इन इलाकों में कई उपभोक्ताओं के बिजली बिलों में बकाया राशि हज़ारों लाखों रुपये में पहुंच चुकी है, जिससे विभाग के पास अब भुगतान त्वरित करने के लिये कड़े निर्देश जारी किये हैं।

महावितरण के नांदेड प्रभाग में घरेलू, वाणिज्यिक, औद्योगिक और अन्य श्रेणियों के ग्रहाकों पर लगभग 758 करोड़ रुपये से अधिक बिजली बकाया है। इस राशि में दीवाबत्ती व पानी-पुरवठा जैसी कुछ आपूर्ति श्रेणियाँ शामिल नहीं हैं, जबकि इनका भी प्रभाव गांवों में देखा जा रहा है।

महावितरण प्रशासन ने अब उन 40 गावों को विशेष रडार पर रखा है जहां बकाया अधिक है और ग्राहकों से बकाया बिजली बिल तुरंत भुगतान करने का निर्देश दिया है। विभाग ने चेतावनी दी है कि यदि बकाया राशि समय पर नहीं भरी गई तो बिजली आपूर्ति कटौती, जुर्माना और अन्य वसूली कार्रवाइयां लागू की जा सकती हैं। स्थानीय स्तर पर कई गांवों में वसूली टीमों को तैनात भी किया गया है ताकि बकाया एकत्र किया जा सके और वितरण सेवा प्रभावित न हो।

स्थानीय ग्रामीणों का कहना है कि इन क्षेत्रों में बिजली का नियमित उपयोग तो हो रहा है, लेकिन बकाया राशि के भुगतान में देरी व आर्थिक कठिनाइयों के कारण उपभोक्ता बिल समय पर नहीं चुका पा रहे हैं। कुछ ग्रामीणों ने महावितरण से किस्तों में भुगतान या आसान सुविधा उपलब्ध कराने की मांग भी की है ताकि वे समय पर बकाया चुका सकें और आपूर्ति कटौती से बच सकें।

महावितरण की यह सख्त अपील राज्य में बढ़ती बिजली बकाया समस्या से निपटने की दिशा में एक अहम कदम मानी जा रही है और विभाग उपभोक्ताओं से सहयोग का आग्रह भी कर रहा है ताकि वितरित सेवा स्थिर और सुचारू बनी रहे।

नांदेड में विधायक बालाजी कल्याणकर ने BJP पर लगाया गंभीर आरोप: कहा- 'भाजपा ने हमारे शिवसेना उम्मीदवारों को पाला बदलने के लिए प्रेरित किया'

संवाददाता |

नांदेड: नांदेड की स्थानीय निकाय चुनावी राजनीति में भाजपा और शिवसेना (शिंदे गुट) के बीच बढ़ते तनाव के बीच विधायक बालाजी कल्याणकर ने भाजपा पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने दावा किया है कि भाजपा ने शिवसेना के अधिकृत उम्मीदवारों को अपने पक्ष में खींच लिया और उनसे समर्थन ले लिया, जिससे गठबंधन में दरार पैदा हुई है।

कल्याणकर के अनुसार, चुनावी मैदान से एक बार जब नामांकन वापस लेने की प्रक्रिया पूरी हो गई, तो भाजपा की सक्रिय भूमिका सामने आई, जिसने कुछ शिवसेना उम्मीदवारों को भाजपा के समर्थन में शामिल होने के लिए प्रेरित किया। इस पर उन्होंने सख्त शब्दों में कहा कि यह गठबंधन की भावना के खिलाफ है और भाजपा ने 'हमारे उम्मीदवार चोरी करने' की कोशिश की है। इस आरोप के बाद स्थानीय राजनीतिक माहौल में हलचल देखने को मिली है, जहां सहयोगी दलों के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है और आगामी चुनावी रणनीतियों पर सवाल उठ रहे हैं।

इम्तियाज जलील ने संजय शिरसाट पर किया तीखा पलटवार, कहा- "नीतिमत्ता सिखाने वाले पहले खुद देखें"

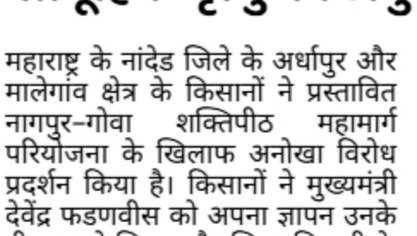

छत्रपति संभाजीनगर (महाराष्ट्र): एमआईएम नेता इम्तियाज जलील ने शिवसेना (शिंदे गुट) नेता संजय शिरसाट पर तीखा हमला बोला है, कहा कि "नीतिमत्ता सिखाने वाले पहले खुद अपनी नीतिगत कार्यों पर विचार करें।" जलील ने आरोप लगाया कि 65 स्थानों पर बिनविरोध निर्वाचित होना लोकशाही की हत्या का प्रतीक है और प्रशासन तथा महायुति सरकार पर गुंडागर्दी का आरोप लगाया।

पत्रकार सम्मेलन में जलील ने कहा कि शिरसाट जैसे लोग, जो खुद राजनीतिक विवादों में शामिल हैं, दूसरों को नैतिकता सिखाने का अधिकार नहीं रखते। उन्होंने यह भी कहा कि एमआईएम में हुए आंतरिक मतभेद के बावजूद पार्टी का महत्व बड़ा है और अगर किसी को नाराज़गी है, तो उसका असर पार्टी को नहीं देना चाहिए।

जलील के बयान का यह राजनीतिक पृष्ठभूमि स्थानीय चुनावों और शक्ति समीकरण के बीच आया है, जिससे दोनों दलों के बीच विवाद और सार्वजनिक बहस तेज हुई है।

परभणी महापालिका चुनाव: शिंदे सेना समेत चार दलों के 5 उम्मीदवारों ने अंतिम दिन नामांकन वापस लिया

परभणी (महाराष्ट्र): परभणी महानगरपालिका चुनाव 2026 के नामांकन वापस लेने के अंतिम दिन राजनीतिक हलचल तेज रही, जिसमें शिंदे सेना, कांग्रेस, भाजपा और जनसुराज्य के कई उम्मीदवारों ने अपनी उम्मीदवारी वापस ले ली। यह रणनीतिक कदम चुनावी समीकरण को प्रभावित कर रहा है और आगामी मुकाबलों का स्वरूप बदल सकता है।

रिपोर्ट के अनुसार, शिंदे सेना के दो उम्मीदवारों ने मैदान से बाहर होने का फैसला किया, जबकि कांग्रेस का एक, भाजपा का एक और जनसुराज्य का एक उम्मीदवार भी प्रतिस्पर्धा से हट गया। विशेष रूप से प्रभाग 1 और 12 में गठबंधन के कारण उम्मीदवारों की माघार ने विभिन्न दलों के रणनीतिक समीकरण को स्पष्ट किया है। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि इन

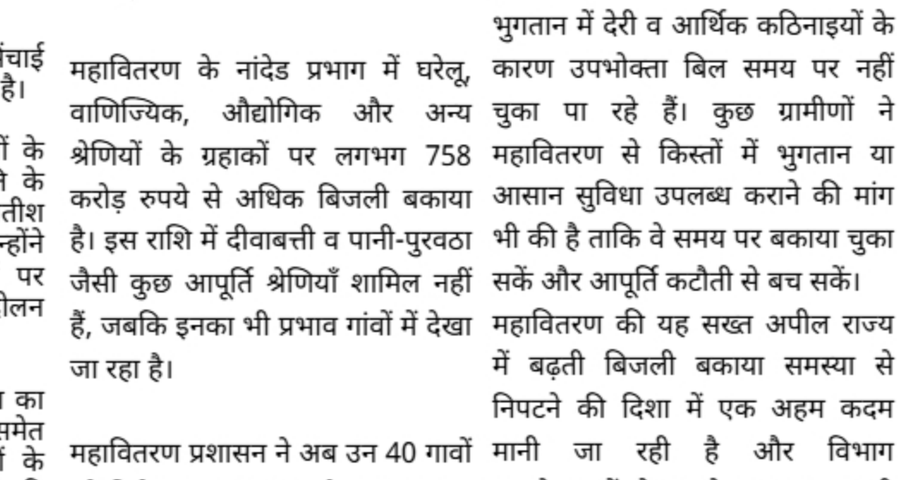

प्रत्याशियों की वापसी से पहले से चल रहे गठबंधन कांग्रेस-शिंदे सेना (UBT), भाजपा-शिंदे सेना (महायुति) और अन्य दलों के बीच चुनावी समीकरण और प्रतिस्पर्धा पर असर पड़ेगा। कुछ वार्डों में गठबंधन के कारण उम्मीदवारों की वापसी ने पार्टी रणनीतियों में फेरबदल कर दिया है, जबकि अन्य वार्डों में चुनौती जारी है।

उम्मीदवारों की वापसी के बाद अब 16 वार्डों में लगभग 411 उम्मीदवार चयनित हैं, और अधिकांश पार्टियाँ चुनाव प्रचार के अंतिम चरण में सक्रिय हो रही हैं। यह भी देखा जा रहा है कि पार्टियों ने बागी उम्मीदवारों को मनाने की कोशिश की है ताकि चुनावी समन्वय कायम रहे।

नांदेड : नगीनाघाट में मामूली विवाद के बाद फायरिंग, दो युवक घायल

नांदेड | नांदेड शहर के नगीनाघाट परिसर में शनिवार शाम आपसी तुलना को लेकर शुरू हुआ एक मामूली विवाद देखते ही देखते गंभीर हिंसक घटना में तब्दील हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि मामला फायरिंग और तलवारबाजी तक जा पहुंचा। इस घटना में दो युवक घायल हो गए, जिसके बाद इलाके में कुछ समय के लिए तनावपूर्ण स्थिति बनी रही।

फायरिंग में घायल युवक को नांदेड के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। चिकित्सकों के अनुसार उसकी हालत फिलहाल स्थिर है। चर्चा है कि घायल युवक विवाद को शांत कराने और दोनों पक्षों के बीच समझौता कराने के उद्देश्य से वहां पहुंचा था, लेकिन हालात बिगड़ने से वह खुद हिंसा का शिकार हो गया। चुनावी पृष्ठभूमि में नांदेड में हुई इस घटना से शहर में तरह-तरह की अफवाहें भी फैलने लगी थीं।

इस घटना में कमलप्रीत सिंह अमरजीत सिंह सिद्धू के पैर में गोली लगी है, जबकि परमजीत सिंह चावला को लाठी से चोटें आई हैं। दोनों का इलाज जारी है।

नांदेड पुलिस सूत्रों के अनुसार, पंजाब से आए कुछ व्यक्तियों का एक ट्रैवल्स चालक और कार चालक के साथ किसी बात को लेकर विवाद हुआ था। बातचीत के दौरान एक-दूसरे की तुलना को लेकर बहस बढ़ती गई और अंततः मामला हिंसक हो गया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को नियंत्रित किया और मामले की गंभीरता से जांच शुरू कर दी है। इलाके में अतिरिक्त पुलिस बंदोबस्त तैनात किया गया है।

स्वाधिकारी नंदिग्राम टाईम्स (नांदेड़) के मुद्रक, प्रकाशक एवं संपादक शेख जहूर शेख अहेमद द्वारा सहारा डिजाइनिंग एंड ऑफसेट प्रिंटिंग प्रेस, वाजेगांव, ता. व जि. नांदेड़ में मुद्रित तथा दैनिक नंदिग्राम टाईम्स, मुल्लाह मार्केट, खवी बिल्डिंग, नगरेश्वर मंदिर, नांदेड़–431604 (महाराष्ट्र) के कार्यालय से प्रकाशित। RNI-MAHHIN/2016/69743 मोबाइल संपर्क: 9921100075 | Email: ntinfodesk@gmail.com (वाद-विवाद हेतु न्यायक्षेत्र: नांदेड़ न्याय कक्षा में।)